इस जहा की सबसे मंहगी चीज एहसास जो दुनियां के हर इंसान के पास नहीं।
– अज्ञात

राजनीतिक समीकरण तैयार

इस बिल से बीजेपी को एक नया वोटबैंक मिलने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि करीब एक लाख गैर मुस्लिम शरणार्थी तत्काल भारतीय नागरिकता की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

चंदर बिष्ट

नागरिकता संशोधन बिल (कैब) लोकसभा में भारी मतों से पास हो गया। इसके पक्ष में जैसा राजनीतिक समीकरण तैयार हुआ है, उससे लगता है कि राज्यसभा से भी पास होने में इसको किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बढ़ती मंदी, घटते जीडीपी और कई राज्यों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन से मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई थी। इस बिल के जरिए खेले गए मजबूत हिंदुत्व कार्ड ने उसे वापस फ्रंटफुट पर ला दिया है।

विधेयक को इसीलिए आनन–फानन कैबिनेट से पास कराकर संसद में पेश किया गया। इससे बीजेपी ने हिंदुत्व वोट बैंक को एकजुट करने में सफलता हासिल की, साथ ही शिवसेना और जेडीयू जैसे परिधि पर बैठे दलों को सकते में डाल दिया। शिवसेना उससे नाता तोड़ चुकी है जबकि जेडीयू से उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी के कमजोर होते आधार को देखकर शायद वह अलग स्टैंड ले। लेकिन दोनों को इस बिल के पक्ष में आना पड़ा। इससे साफ हो गया कि शिवसेना एक अपवाद है, एनडीए के बाकी सहयोगी दल अभी बीजेपी से अलग होने का जोखिम नहीं ले पाएंगे। इससे बीजेपी विरोधी गठबंधन बनने की संभावना फिलहाल कमजोर पड़ गई है। बिल की एक बड़ी बाधा नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जहां इसका विरोध हो रहा है। हालांकि सरकार ने इस उलझन का भी एक तोड़ खोजा है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में आने वाले पूर्वोत्तर भारत के इलाकों को नागरिकता संशोधन विधेयक में छूट दी गई है। इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कई इलाके आते हैं।

इसके अलावा उन राज्यों को भी कैब से छूट मिली है, जहां इनर लाइन परमिट (आईएलपी) लागू है। अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिजोरम इसके तहत आते हैं और मणिपुर को इसमें लाने की प्रक्रिया जारी है।

सिक्किम को लेकर असमंजस जरूर है पर उसके कुछ राजनेताओं के बयान से लगता है कि उसे भी कैब से छूट दी जाएगी। इस बिल से बीजेपी को एक नया वोटबैंक मिलने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि करीब एक लाख गैर मुस्लिम शरणार्थी तत्काल भारतीय नागरिकता की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस संख्या में आगे और इजाफा हो सकता है।

बहरहाल, अपना जनाधार बढ़ाने के चक्कर में बीजेपी देश को एक संकट की ओर धकेल रही है। एक तरफ हमारे देश में घुसपैठियों की समस्या है, जिससे हम निजात पाना चाहते हैं क्योंकि हम पर पहले से ही जनसंख्या का बोझ है। यह बोझ कम करने की कवायद एनआरसी के जरिये की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कैब के जरिये जनसंख्या बढ़ाने का रास्ता भी खोला जा रहा है। यह कानून बनने से गैर–मुस्लिम घुसपैठियों को राहत मिलेगी जबकि देश का मूलनिवासी मुसलमान जरूरी दस्तावेज न जुटा पाने के कारण फंस जाएगा। इस विडंबना को समाप्त करना तो दूर, इसे समझने में भी सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई देती।

आनंद का अनुभव

धर्म-दर्शन

मनमोहन। भाग्यवश, वो सारे संत और महात्मा जिन्होंने आगे तक की यात्रा की है, उन्होंने अभिलेख के रूप में अपना अनुभव हमारे लिये छोड़ा है. वो वर्णन करते हैं कि हमारी आत्मा भगवान के एक बूंद के समान है. आध्यात्म के रूप में, 'ध्यान' ही वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आत्मा को अपने संपर्क में लाया जा सकता है. इस संसार में हम जिसे अपनी चेतन अवस्था समझते हैं, वह आध्यात्म के उत्कृष्ट चेतना अवस्था की तुलना में एक सुसूप्तावस्था है. यह बौद्धिक ज्ञान नहीं है. इस आंतरिक ज्ञान तक पहुंचकर हम जीवन को एक नये दृष्टिकोण से देखते हैं. हमें यह एहसास होता है कि यह दुनिया एक अस्थायी घर है और जब हम एक गुरु की मदद से आध्यात्मिक रूप से जागते हैं तो हमें अपनी आध्यात्मिक प्रकृति और सच्चे घर का ज्ञान हो जाता है।

संपादकीय

विरोधियों को भी गल

देश में मोदी सरकार–2 की विधिवत शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि उनके शासन में भी राष्ट्रपिता को यथोचित सम्मान मिलता रहेगा। अपने इस कदम के जरिये उन्होंने चुनावी माहौल में पैदा हुई इस आशंका को निर्मूल कर दिया कि दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई बीजेपी महात्मा गांधी से जुड़े प्रतीकों और नीतियों को खास तवज्जो नहीं देगी। यह भी कि अटल जी की सबको साथ लेकर चलने और अपने विरोधियों को भी गले लगाने वाली सोच इस सरकार का दिशा निर्देशक तत्व बनी रहेगी।

प्रधानमंत्री का वॉर मेमोरियल के आगे सिर झुकाना राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर उनकी सरकार की प्रतिबद्धता के अलावा इस संकल्प का भी द्योतक है कि भारतीय सुरक्षाकर्मियों को हर तरह की सहूलियत और इज्जत बख्शी जाएगी। बिम्सटेक सदस्य देशों के नेता इसके खास आकर्षण रहे। बंगाल की खाड़ी से जुड़े सात देश भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान इस संगठन में शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में बिम्सटेक को मजबूती से खड़ा करने में भारत का अहम योगदान रहा है। नरेंद्र मोदी की वापसी से इसे और फलने–फूलने का मौका मिलेगा। भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब एक पार्टी के पूर्ण बहुमत वाली कोई गैर कांग्रेसी सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। यह महज एक चुनावी जीत नहीं, सामाजिक–आर्थिक विकास की एक यात्रा है, जिसके सूत्रधार नरेंद्र मोदी बने। देश की 130 करोड़ जनता ने उन्हें दोबारा चुनकर इस यात्रा को जारी रखने का निर्देश दिया है। उम्मीद करें कि जो काम, जो सपने पहले कार्यकाल में अधूरे रह गए वे इस दौर में जरूर पूरे होंगे।

पिछले तीन दशकों से भारत दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबों का घर बना हुआ था। लेकिन अनेक अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने माना है कि 2022 तक यहां 5 फीसदी ही अत्यंत निर्धन लोग बचेंगे।

अत्यधिक निर्धनता का पैमाना

लता जोशी

हमें अपनी व्यवस्था की आलोचना करने की आदत सी हो गई है लिहाजा कई बार हम अपनी उपलब्धियों को देख ही नहीं पाते। लेकिन आगे बढ़ने के प्रति उत्साह बना रहे, इसके लिए कभी–कभी हमें ठहरकर सकारात्मक भाव से भी चीजों को देखना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के सामने आई भारत के विकास की कहानी कोई हवा–हवाई बात नहीं है। अलग–अलग स्रोतों से आए आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। जैसे अगले दस सालों में भुखमरी का कलंक भारत के माथे से मिटने जा रहा है।

पिछले तीन दशकों से भारत दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबों का घर बना हुआ था। लेकिन अनेक अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने माना है कि 2022 तक यहां 5 फीसदी ही अत्यंत निर्धन लोग बचेंगे। यहां अत्यधिक निर्धनता का पैमाना है एक व्यक्ति की रोजाना की औसत कमाई 1.9 डॉलर (135 रुपये) या उससे कम। यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया तो अत्यंत विरल अपवादों को छोड़कर भूख से कोई नहीं मरेगा। दरअसल 1990 के बाद से निर्धनता कम होने की प्रक्रिया में तेजी आई और 2004–05 में इसने रफ्तार पकड़ी। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त

राशन उपलब्ध कराने की योजनाएं पिछले वर्षों में शुरू हुईं, जिनका नतीजा अब देखने में आ रहा है।

हालांकि हमारे यहां विकास प्रक्रिया बहुत असंतुलित रही है। इसमें काफी लोगों को भुखमरी से उबारा गया लेकिन इसका ज्यादा लाभ उस तबके ने उठाया जो पहले से ही लाभान्वित था। यानी अमीर और अमीर होता गया। गरीब भी आगे बढ़ा लेकिन अमीरों की रफ्तार ज्यादा तेज रही। नतीजा यह हुआ कि समाज में असमानता बढ़ती गई। 2018 के एक सर्वे के अनुसार भारत के 1 फीसदी सबसे अमीर लोगों के पास देश की 73 फीसदी संपत्ति है। जाहिर है, गरीबी उन्मूलन का अगला चरण यह होना चाहिए कि लोग जीवन निर्वाह की स्थिति से ऊपर उठें। यानी उन्हें पौष्टिक भोजन, कामकाजी शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जाए। विकास प्रक्रिया की कसौटी भी यही होगी।

इस प्रक्रिया का ही नतीजा है कि भारतीयों की जीवन प्रत्याशा (लाइफ एक्सपेक्टेन्सी) लगातार बढ़ रही है। 1951 में यह 32 वर्ष थी, जो 2013 में 69 वर्ष हो गई। इसका कारण यह है कि कई बीमारियों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इन पर दुनिया भर में हुए शोध का फायदा भारत को भी हुआ है। सभी जरूरी दवाएं और आधुनिक चिकित्सा देश में उपलब्ध है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार जारी है। लेकिन इस क्षेत्र में लक्ष्य यह होना चाहिए कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधा समाज के हर नागरिक को मयस्सर हो। इसी तरह युवाओं की साक्षरता दर 1951 में 18 प्रतिशत थी, जो 2015 में 86 प्रतिशत हो गई। हालांकि साक्षरता का कोई मायने तभी है जब इससे लोगों की सामाजिक–आर्थिक हैसियत बदले। जाहिर है, हमें अपने लक्ष्य भी बदलने होंगे।

सूडोकु नवताल-5191

सरल

6					7			
		8	2				7	5
	4			3				6
	7	1			2		5	
8				4				3
	2		8			9	6	
2				8			3	
4	3				9	8		
			3					9

Jagrutidaur.com, Bangalore

सूडोकु नवताल -5190 का हल

7	4	6	9	1	5	8	3	2
1	5	2	8	3	7	4	6	9
9	3	8	2	6	4	7	1	5
8	6	4	7	9	1	5	2	3
5	2	7	3	4	6	9	8	1
3	9	1	5	8	2	6	7	4
2	7	9	1	5	8	3	4	6
6	1	5	4	7	3	2	9	8
4	8	3	6	2	9	1	5	7

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

अपना ब्लॉग

सिलेक्टविजम का चश्मा उतारने का वक्त है

शेफाली श्रीवास्तव। उन्नाव में रेप पीड़िता की मौत हो गई। हैदराबाद में महिला डॉक्टर की जली हुई लाश मिली थी३मुजफ्फरपुर में युवती को जलाया गया, दरभंगा में 5 साल की बच्ची से रेप हुआ, झारखंड में लॉ स्टूडेंट के साथ गनपॉइंट पर रेप हुआ। मालदा में भी हैदराबाद जैसा हुआ३अभी पूरा देश गुस्से में उबल रहा है, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी जा रही हैं। हर दिन ये ट्रेंड हो रहा है.. कैंडल मार्च, अनशन– प्रदर्शन सब हो रहा है लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि कुछ समय बाद ये सब भुला दिया जाएगा और फिर किसी अगली घटना का इंतजार किया जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर हम इतने सिलेक्टिव हैं कि हमारे अंदर का 'ऐक्टिविस्ट' अब सीजनल हो गया है। लगातार लाइमलाइट में आ रहीं रेप घटनाओं पर आक्रोशित होने से पहले जरा सोचिए क्या आपको वाकई गुस्सा दिखाने का हक है? गंभीर अपराध छोड़ दीजिए, अपने आस–पास जब आप किसी महिला को असहज देखते हैं तो कितनी बार आवाज उठाते हैं, और कितनी बार नजरें घुमा लेते हैं। नहीं तो कभी खुद ही घूरना शुरू कर देते हैं।